प्रकाशन का 47 वां वर्ष

सरोकारी पत्रकारिता के लिए समर्पित

शैल

निष्पक्ष एवं निर्भीक साप्ताहिक समाचार

ई – पेपर

www.facebook.com/shailsamachar

प्रदेश का पहला ऑनलाईन साप्ताहिक

वर्ष 47 अंक – 30 पंजीकरण आरएनआई 26040/74 डाक पजींकरण एच. पी./93 /एस एम एल Valid upto 31-12-2023 सोमवार 18 – 25 जुलाई 2022 मूल्य पांच रूपए

चुनाव पूर्व सर्वेक्षणों में नहीं बनी भाजपा की सरकार

- समय – समय पर आये पत्र बम्बों ने बिगाड़ा गणित
- अधिकांश मंत्रियों की वापसी संदिग्ध
- जिस महंगाई ने उपचुनाव हराये उसके चलते आम चुनाव कैसे हो सकते हैं सुरक्षित
- खीमी, कुठियाला और इन्दु वर्मा के बाद यह आंकड़ा एक दर्जन होने की संभावना

शिमला/शैल। क्या हिमाचल में भाजपा सत्ता में वापसी कर पायेगी? क्या भाजपा हिमाचल कांग्रेस में तोड़फोड़ कर पायेगी? यह सवाल इन दिनों फिर पूछे जाने लग पड़े हैं। क्योंकि जब भाजपा चारों उपचुनाव हार गयी थी तो इस हार के लिये महंगाई को जिम्मेदार ठहराया गया था। अब यह महंगाई और बढ़ गयी है लेकिन जयराम के मंत्रिमण्डलीय सहयोगी वीरेन्द्र कंवर महंगाई को कोई मुद्दा ही नहीं मानते हैं। इस आश्य का उनका ब्यान छपा है। वैसे अब जब साधारण खाद्य सामग्री पर जीएसटी लगा दिया गया है तो स्वभाविक रूप से महंगाई बढ़ेगी ही। लेकिन इस महंगाई पर अभी तक मुख्यमंत्री ने मुंह नहीं खोला है। तय है कि जब महंगाई से तंग आकर जनता उपचुनाव हरवा सकती है तो अब जब सरकार बदली जा सकती है तो जनता क्यों पीछे रहेगी। उपचुनाव में मिली हार के बाद यह लगातार छपता रहा है कि जिन मंत्रियों का रिपोर्ट कार्ड अच्छा नहीं है उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है। उनके विभाग बदले जा सकते हैं। चुनाव में तीन दर्जन लोगों के टिकट बदले जायेंगे। उप चुनावों के बाद इस आश्य का जो कुछ भी छपा वह भले ही सही नही हुआ हो लेकिन इससे यह संदेश अवश्य गया है कि सरकार और संगठन में सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। जब उत्तराखंड में धामी की हार के बाद भी उसे मुख्यमंत्री बना दिया गया तब हिमाचल में भी यह मांग उठी की धूमल की हार के कारणों की जांच की जाये। इस मांग को किस तरह नकारा गया और यहां तक कह दिया गया कि 2017 में पुराने नेतृत्व और नीति को खत्म करके नया नेता और नीति लायी गयी है। इसका असर धूमल समर्थकों पर क्या हुआ होगा इसका अन्दाजा लगाना कठिन नहीं होगा। बल्कि जब इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए दो निर्दलीय विधायकों को भाजपा में शामिल किया गया इससे धूमल समर्थकों रविन्द्र रवि और गुलाब सिंह ठाकुर को हाशिये पर धकेल दिया गया। इससे भी भाजपा के अन्दर खेमे बाजी होने का ही प्रमाण मिलता है। जयराम के कार्यकाल में पार्टी के अपने ही कार्यकर्ताओं और नेताओं ने सरकार के खिलाफ पत्र बम्बों के माध्यम से नेतृत्व और हाईकमान को समय – समय पर आगाह करने के प्रयास हुये हैं वह भी किसी से छिपा नहीं है। भले ही कांग्रेस सरकार के खिलाफ आरोपपत्र न ला पायी हो लेकिन जो मुद्दे इन पत्र बम्बों में उछले हैं उनका असर विपक्ष के आरोपों से कहीं ज्यादा है। क्योंकि चुनाव के दौरान यह पत्र बम फिर से मुद्दा बन जायेंगे इस संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है। चंडीगढ़ में एक मंत्री की पत्नी के पर्स की चोरी होने पर दर्ज हुई एफआईआर का परिणाम आज तक सामने नहीं आया है। इन पत्र बम्बों के माध्यम से मुद्दे आज तक अपनी जगह खड़े हैं। बल्कि इसी का परिणाम है कि अब भाजपा छोड़ नेता कांग्रेस में जाने लग पड़े हैं। खिमी राम, मनोज कृठियाला और अब इन्दु वर्मा सबका कांग्रेस में जाना यह इंगित करता है कि निकट भविष्य में यह लाइन उम्मीद से ज्यादा लंबी हो सकती है। भाजपा तो यह दावे ही करती रही है कि कांग्रेस से लोग भाजपा में आयेंगे जैसा कि अन्य प्रदेशों में हो रहा है। लेकिन हिमाचल में इससे उलट हो रहा है और इसका प्रदेश नेतृत्व के पास कोई जवाब नहीं है। बल्कि इस परिदृश्य में जो चुनाव पूर्व चार सर्वेक्षण हुए उनके परिणाम भी वायरल हो चुके हैं। किसी भी सर्वेक्षण में भाजपा सत्ता में वापसी नहीं कर पायी है। सबसे बड़े जिले कांगड़ा में दो या तीन के आंकड़े से आगे नहीं बढ़ पायी है। चंबा, ऊना, हमीरपुर और बिलासपुर में शून्य होने की संभावनाएं हैं। जनजातीय क्षेत्रों में भी शून्य का सर्वे है। अधिकांश मंत्री सुरक्षित नहीं माने जा रहे हैं। केवल गोदी मीडिया की रिपोर्टों में स्थिति संतोषजनक है।

क्या बिना काम के बैठाना जिम्मेदारी में समकक्षता है

सरकार के आदेश से उभरी चर्चा

शिमला/शैल। जयराम सरकार ने अभी 14 तारीख को 1987 बैच के आईएएस अधिकारी राम सुभाग सिंह को मुख्य सचिव के पद से हटाकर उनके स्थान पर 1988 बैच के आर.डी. धीमान को इस पद पर तैनात किया है। वैसे राम सुभाग सिंह की सेवानिवृत्ति जुलाई 2023 में होगी। मुख्य सचिव किसको बनाना है यह मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है। इसमें यही सुनिश्चित किया जाता है यदि किसी जूनियर को इस पद पर तैनाती दी जाती है तो ऐसे में नजरअन्दाज किये जाने वाले सीनियर को उसके जूनियर के तहत पोस्ट न किया जाये। जयराम सरकार ने भी आर.डी. धीमान को मुख्य सचिव नियुक्त करते हुये उनसे सीनियर राम सुभाग सिंह, निशा सिंह और संजय गुप्ता को नजरअंदाज करके इन लोगों को बतौर सलाहकार नियुक्तियां दी। यह नियुक्तियां व्यवहारिक रूप से बिना काम के बैठने वाली होती हैं। क्योंकि कोई भी विभागीय सचिव सलाहकार से सलाह लेने नहीं जाता है। सरकार के रूल्स ऑफ बिजनेस में भी सलाहकार का पद परिभाषित नहीं है। किस स्तर पर कौन सी फाइल सलाहकार को जायेगी ऐसा कुछ भी इन नियमों में प्रदत नहीं है और यह नियम बाकायदा विधानसभा से पारित हैं और गोपनीय माने जाते हैं। इस परिपेक्ष में जब यह सामने आया कि इन तीनों अधिकारियों को बिना काम के बैठा दिया गया है जबकि नियमों के मुताबिक इन्हें मुख्य सचिव के समकक्ष होना है। यह सामने आते ही एक और आदेश पारित करके इन लोगों को मुख्य सचिव के समकक्ष स्टेटस और जिम्मेदारियां दी गयी। इस आशय का आदेश अलग से जारी हुआ है। लेकिन व्यवहार में इन अधिकारियों के पास कोई फाइल आने का प्रावधान ही रूल्स ऑफ बिजनेस में नहीं है। ऐसे में कोई भी अधिकारी बिना काम के जिम्मेदारी में भी मुख्य सचिव के समकक्ष कैसे हो जायेगा? यह सवाल सचिवालय के गलियारों से लेकर सड़क तक बराबर चर्चा में चल रहा है। क्योंकि यह अधिकारी और इनके कार्यालयों में तैनात कर्मचारी कई लाखों में वेतन ले रहे हैं। लेकिन सभी बिना काम के बैठे हैं। मान सम्मान तो बिना काम के बैठ कर भी मिलना माना जा सकता है। लेकिन बिना काम के भी जिम्मेदारी में भी समकक्षता कैसे हो जायेगी यह रहस्य बना हुआ है।

यह माना जा रहा है कि इस स्तर के तीन – तीन अधिकारियों को चुनावों से 4 माह पहले बिना काम के बैठा कर प्रदेश की जनता और पूरे प्रशासन को जो संदेश अपरोक्ष में जा रहा है वह सरकार की चुनावी सेहत के लिये बहुत घातक सिद्ध होगा। क्योंकि नजरअन्दाज हुये अधिकारी स्वभाविक है कि वह सरकार के अब शुभचिंतक नहीं हो सकते। इस स्तर के अधिकारियों के पास सरकार को लेकर जो जानकारियां रही होंगी वह चुनावों के दौरान बाहर आकर सरकार के लिये कैसी कठिनाइयां पैदा करेंगे यह तो आने वाला समय ही बतायेगा जिन सलाहकारों ने चुनावों से चार माह पहले ऐसी सलाह दी है उन्होंने इससे पहले क्या – क्या किया होगा यह अंदाजा लगाना कठिन नहीं होगा।

Government of Himachal Pradesh
Department of Personnel
Appointment-I
****

No.Per(A-I)B(2)-1/2001-Part Dated Shimla-2, the 14th July, 2022.

NOTIFICATION

The Governor, Himachal Pradesh, in terms of the provisions of the Rule 12(1) of the IAS (Pay) Rules, 2016, is pleased to declare the following ex-cadre posts, equivalent in status and responsibilities to the post of Chief Secretary to the Government of Himachal Pradesh which is included in the schedule-II of the Rules ibid, with immediate effect, till the following officers continue to hold these posts:-

Sl. No.	Name of the officer	Name of the ex-cadre post
1.	Shri Ram Subhag Singh, IAS (HP:1987)	Principal Advisor (Administrative Reforms) to the Government of Himachal Pradesh, Shimla.
2.	Ms. Nisha Singh, IAS (HP:1987)	Principal Advisor (Training & FA) to the Government of Himachal Pradesh, Shimla.
3.	Shri Sanjay Gupta, IAS (HP:1988)	Principal Advisor (Redressal of Public Grievances) to the Government of Himachal Pradesh, Shimla.

By Order
Prabodh Saxena
Additional Chief Secretary (Personnel) to the
Government of Himachal Pradesh.

Endst. No. As above Dated Shimla-171 002, the 14th July, 2022.
Copy to:-
1. All the officers concerned (By Name).
2. The Principal Secretary (SAD&GAD) to the Government of Himachal Pradesh, Shimla-171002.
3. The Director, H.P. Institute of Public Administration, Fairlawns, Shimla-12.
4. The Pr. Accountant General (Audit), HP, Shimla-3.
5. The Pr. Accountant General (A&E), HP, Shimla-3.
6. The Controller (F&A), Department of Personnel, HP Secretariat, Shimla-2.
7. Personal Files/Guard file/Spare copies.

14/7/22
(Amarjeet Singh)
Special Secretary (Personnel) to the
Government of Himachal Pradesh
Ph. No. 0177-2621894
Email Id: persbr1-hp@nic.in

*****

राज्यपाल ने मिंजर मेले का किया विधिवत शुभारंभ

लोक संस्कृति के संरक्षण पर दिया बल

शिमला/शैल। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश का गौरवशाली इतिहास और समृद्ध लोक परम्पराएं प्रदेश की उन्नति और तरक्की में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। राज्यपाल चम्बा जिले के एतिहासिक मिंजर मेला के शुभारंभ अवसर पर बतौर मुख्य अतिथि बोल रहे थे। राज्यपाल के रूप में आर्लेकर का यह चम्बा जिले का पहला दौरा है और पिछले कई वर्षो के बाद राज्यपाल मिंजर मिला के शुभारम्भ अवसर पर चम्बा पहुंचे हैं।

राज्यपाल ने कहा कि ऐतिहासिक मिंजर मेला की अपनी अलग पहचान है। ज़िला की समृद्ध लोक कला एवं संस्कृति के संरक्षण व संवर्धन और सामाजिक सौहार्द को बनाए रखने पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए उन्होंने मेले के सफल आयोजन में आधुनिकता के उचित समावेश पर बल दिया। उन्होंने कहा कि चंबा की समृद्ध लोक संस्कृति है। इस संस्कृति को पुरातन समय से लोगों द्वारा सहेजा जा रहा है। उन्होंने लोगों का आहवान किया कि स्थानीय पारंपारिक लोक संस्कृति व सामाजिक सौहार्द को वे इसी तरह संरक्षित रखा जाना चाहिए।

आर्लेकर ने ज़िला की प्रसिद्ध कलाकृति चंबा रुमाल और चंबा चप्पल का जिक्र भी किया। उन्होंने कहा कि चंबा चप्पल और चंबा रुमाल को भौगोलिक संकेत (जीआई टैग) मिलने से चंबा को प्रसिद्धि मिल रही है। उन्होंने कहा कि ऐतिहासिक मिंजर मेला को अंतरराष्ट्रीय मेला का दर्जा दिए जाने को लेकर प्रदेश सरकार आवश्यक कार्रवाई कर रही है।

इससे पूर्व, राज्यपाल ने चंबा के पारंपरिक कूंजड़ी मल्हार गायन के बीच ध्वजारोहण कर मिंजर मेला का विधिवत शुभारंभ किया। उन्होंने बाद में विभिन्न विभागों और सामाजिक संस्थाओं द्वारा लगाई गई प्रदर्शनियों का शुभारंभ और अवलोकन भी किया।

चंबा नगर परिषद अध्यक्ष नीलम नैयर ने राज्यपाल को मिंजर भेंट की।

मिंजर मेला आयोजन समिति की ओर से उपायुक्त एवं अध्यक्ष डीसी राणा ने राज्यपाल को सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि समिति द्वारा रात्रि सांस्कृतिक संध्या में हर वर्ग की रुचि का ध्यान रखा गया है। उन्होंने कहा कि चंबा जिला और प्रदेश के अन्य जिलों के कलाकारों को भी 8 दिनों तक चलने वाले इस मेले में अपनी प्रस्तुतियां देने का मौका मिलेगा।

इस मौके पर मिंजर मेला खेलकूद प्रतियोगिताओं का भी शुभारम्भ हुआ। राज्यपाल ने मिंजर मेला खेलकूद प्रतियोगिताओं के विधिवत शुरू होने की घोषणा भी की। पुलिस अधीक्षक अभिषेक यादव ने उन्हें मिंजर मेला खेलकूद समिति की ओर से सम्मानित किया।

समारोह में विधानसभा उपाध्यक्ष डॉ. हंसराज, विधायक पवन नैयर, जिला भाजपा अध्यक्ष जसवीर नागपाल, अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी अमित मेहरा, नगर परिषद अध्यक्ष नीलम नैयर समेत नगर परिषद के पार्षद, विभिन्न विभागों के अधिकारी और गणमान्य लोग इस अवसर पर उपस्थित थे।

राज्यपाल ने रक्तदान वैन को हरी झंडी दिखा कर खाना किया

शिमला/शैल। राज्यपाल राजेन्द्र विश्वनाथ आर्लेकर ने राजभवन से 3 काउच रक्तदान वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। हिमाचल प्रदेश में पहली बार राज्य रेडक्रॉस सोसायटी के माध्यम से रक्तदान के लिए व्यापक सुविधाओं वाली बस जैसी रक्तदान वैन की व्यवस्था की गई है। यह वैन भारतीय रेडक्रॉस सोसायटी के माध्यम से राज्य रेडक्रॉस सोसायटी को उपलब्ध करवाई गई है। राज्य रेडक्रॉस द्वारा इसे सोलन जिला में ब्लड बैंक नालागढ़ के अंतर्गत संचालित किया जाएगा। यह वैन क्षेत्रीय स्तर पर रक्त एकत्रित कर ब्लड बैंकों को उपलब्ध कराएगी।

इस अवसर पर नालागढ़ की खण्ड चिकित्सा अधिकारी डॉ. मुक्ता रस्तोगी ने राज्यपाल से वैन प्राप्त की।

इस वैन में रक्तदाता पंजीकरण काउंटर, 3 डोनर काउच, एक डोनर बेड, रक्तदाता को आराम के लिए सोफा, डोनर रिफ्रेशमेंट पेन्ट्री, ब्लड बैग रेफ्रिजरेटर, उपकरण भण्डारण कैबिनेट इत्यादि सुविधाएं प्रदान की गई हैं। इंजन चलित एयर कंडीशनर, बैंक पावर के लिए स्प्लिट यूनिट एयर कंडीशनर, जनरेटर इन्वर्टर, ध्वनि प्रसार प्रणाली, सहायक उपकरण के साथ सिलेंडर, एलईडी रूफ लाइट, कोच पंखे और भण्डारण सुविधा आदि प्रदान की गई हैं।

भारतीय रेडक्रॉस सोसायटी की राष्ट्रीय प्रबन्धन समिति की सदस्य और राज्य रेडक्रॉस अस्पताल कल्याण अनुभाग की अध्यक्ष डॉ. साधना ठाकुर, राज्यपाल के सचिव और राज्य रेडक्रॉस सोसायटी के महासचिव राजेश शर्मा, राज्य रेडक्रॉस सोसायटी के सचिव संजीव कुमार और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी इस अवसर पर उपस्थित थे।

उपजाऊ भूमि तक गाद फैलने से रोकने के लिए तंत्र करें विकसित:मुख्यमंत्री

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (बीबीएमबी) और राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए लोगों की सुविधा के दृष्टिगत बीबीएमबी को मंडी जिला के नाचन क्षेत्र की बग्गी-धनोटू-सुन्दरनगर सड़क की मेटलिंग और टारिंग का कार्य करने को कहा।

जय राम ठाकुर ने कहा कि सुंदरनगर में थवाल पुल के काम में तेजी लाई जानी चाहिए और बीबीएमबी को उसके द्वारा निर्मित 40 मीटर मंगलाह पुल के साथ सड़कों के निर्माण पर भी विचार करना चाहिए। उन्होंने कहा कि इससे मंडी जिले के सुंदरनगर, नाचन, बल्ह और सराज विधानसभा क्षेत्रों की कई पंचायतों के लोगों को सुविधा होगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि बीबीएमबी अधिकारियों को परियोजनाओं से उपजाऊ भूमि तक गाद के फैलने को रोकने के लिए एक तंत्र विकसित करना चाहिए। उन्होंने कहा कि किसानों की बेशकीमती जमीन को बचाने के लिए उपयुक्त दीवार लगाने के साथ-साथ अन्य सुरक्षा उपाय किए जाने चाहिए।

जय राम ठाकुर ने कहा कि किसी भी अप्रिय घटना से बचाव के लिए नहर के किनारे क्रैश बैरियर भी लगाए जाएं। उन्होंने बीबीएमबी प्राधिकरण को पंडोह के पास बाखली पुल की मरम्मत और रखरखाव के अलावा पंडोह में इको पार्क की उचित सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भी कहा।

मुख्यमंत्री ने बीबीएमबी के अधिकारियों को लोगों की सुविधा के दृष्टिगत पौंग बांध की बाहरी सीमा के साथ सुरक्षा दीवारों के निर्माण के अलावा क्षेत्र में सड़कों के निर्माण और रखरखाव के लिए भी कहा।

नाचन के विधायक विनोद कुमार, सुंदरनगर के विधायक राकेश जम्वाल और देहरा के विधायक होशियार सिंह ने बीबीएमबी परियोजनाओं के संबंध में अपने विभिन्न मामले उठाए।

बीबीएमबी के अध्यक्ष संजय श्रीवास्तव ने मुख्यमंत्री को आश्वासन दिया कि बोर्ड परियोजना क्षेत्र से संबंधित सभी मुद्दों को सही परिप्रेक्ष्य में लेगा और चल रही परियोजनाओं को समयबद्ध पूरा करना भी सुनिश्चित करेगा।

बैठक में मुख्य सचिव आर.डी. धीमान, निदेशक ऊर्जा हरिकेश मीणा, राज्य सरकार और बीबीएमबी के अन्य वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए।

मुख्यमंत्री ने बिलासपुर में निर्मित ईवीएम और वीवीपैट वेयरहाउस का लोकार्पण किया

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने बिलासपुर में 4.92 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित ईवीएम और वीवीपैट वेयरहाउस का शिमला से वर्चुअल माध्यम द्वारा लोकार्पण किया। इसका शिलान्यास वर्ष 2020 में किया गया था और इस वेयरहाउस को रिकॉर्ड समय अवधि में तैयार किया गया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के सभी जिलों में ईवीएम वेयरहाउस स्थापित किए जा रहे हैं ताकि विशिष्ट मापदण्डों के साथ ईवीएम और वीवीपैट मशीनों को एक साथ एक स्थान पर रखा जा सके।

जय राम ठाकुर ने ईवीएम और वीवीपैट वेयरहाउस के निर्माण सम्बन्धी मामला भारत निर्वाचन आयोग के समक्ष रखने के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का आभार व्यक्त किया। इससे न केवल मशीनों की पूर्ण सुरक्षा सुनिश्चित होगी बल्कि चुनाव प्रक्रिया को निष्पक्ष रूप से पूरा करने में भी सुविधा प्रदान होगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले ईवीएम और वीवीपैट मशीनों को राजकीय महाविद्यालयों या स्कूल परिसरों में रखा जाता था और इस स्थिति में इन मशीनों के लिए सुरक्षा सम्बन्धी व्यवस्था करनी पड़ती थी। उन्होंने कहा कि इससे शिक्षण संस्थानों के कमरों का लम्बे समय तक उपयोग होने के कारण विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित होती थी।

जय राम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश के हर क्षेत्र में अभूतपूर्व विकास सुनिश्चित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा समाज के कमजोर और वंचित वर्गो पर विशेष ध्यान देते हुए उनके उत्थान के लिए विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं शुरू की गई हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश के गठन के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में प्रदेश में 75 कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह आयोजन इन अवधि के दौरान प्रदेश में हुई प्रगति को दर्शाने में सहायक सिद्ध होंगे।

इस अवसर पर ईवीएम और वीवीपैट वेयरहाउस बिलासपुर की मुख्य विशेषताओं पर एक प्रस्तुति भी दी गई।

कार्यक्रम के दौरान खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री राजिंद्र गर्ग, विधायक सुभाष ठाकुर, जे.आर.कटवाल और राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के उपाध्यक्ष रणधीर शर्मा बिलासपुर में उपस्थित थे।

एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत केरल के 50 छात्र पांच दिवसीय छात्र विनिमय कार्यक्रम के लिए शिमला का दौरा करेंगे

शिमला/शैल। राष्ट्रव्यापी आजादी का अमृत महोत्सव-एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत, केरल के 50 छात्र 25 जुलाई को पांच दिवसीय छात्र विनिमय कार्यक्रम के लिए शिमला का दौरा कर रहे हैं। छात्र समूह के साथ कुल छह संकाय सदस्य हैं। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय का प्रौद्योगिकी संस्थान (यूआईटी) इस पांच दिवसीय कार्यक्रम की मेजबानी कर रहा है।

यह कार्यक्रम केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई), नई दिल्ली द्वारा शुरू किया गया है । हिमाचल प्रदेश और केरल इस कार्यक्रम के तहत युग्मित राज्य हैं, जिसका उद्देश्य राज्य/केंद्र शासित प्रदेश की जोड़ी अवधारणा के माध्यम से विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लोगों के बीच परस्पर समझ को बढ़ावा देना और आपसी समझ को बढ़ावा देना है।

निदेशक यूआईटी प्रो. पी. एल. शर्मा ने कहा कि यूआईटी ने केरल से आने वाले छात्रें के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं कर दी हैं । राज्य में अपने पांच दिनों के प्रवास के दौरान, छात्र हिमाचल प्रदेश की संस्कृति, परंपरा, समाज और लोगों के बारे में जानेंगे। वे राज्य के स्थानीय व्यंजनों, फलों और पारंपरिक परिधानों का भी अवलोकन करेंगे।

हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. सत प्रकाश बंसल ने मेजबान संस्थान यूआईटी को अपना पूरा समर्थन दिया और कहा कि भारत में विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में रहने वाले विविध संस्कृतियों के लोगों को एकजुट करने के लिए यह भारत सरकार की एक अच्छी पहल है।

शैल समाचार
संपादक मण्डल

संपादक- बलदेव शर्मा

सयुक्त संपादक:जे.पी.भारद्वाज

विधि सलाहकार: ऋचा

अन्य सहयोगी

राजेश ठाकुर

अंजना

मुख्यमंत्री ने नीति आयोग से मंडी ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे के लिए विशेष सहायता प्रदान करने का आग्रह किया

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने नई दिल्ली में नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी से राज्य से जुड़े विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की।

मुख्यमंत्री ने उन्हें राज्य में हवाई संपर्क को मजबूत करने के लिए राज्य के प्रयासों से अवगत करवाया। उन्होंने कहा कि मंडी में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे के निर्माण के लिए राज्य सरकार और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के बीच संयुक्त उद्यम समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। उन्होंने राज्य में हवाई सम्पर्क को सुदृढ़ करने के लिए वर्तमान वित्त वर्ष के दौरान 1000 करोड़ रुपये के विशेष सहायता अनुदान का भी आग्रह किया।

मुख्यमंत्री ने प्रदेश में औद्योगिक विकास की गति को तेज करने के लिए उपाध्यक्ष से औद्योगिक विकास योजना – 2017 को अगले पांच वर्षों तक बढ़ाने का भी आग्रह किया।

मुख्यमंत्री ने उपाध्यक्ष को हिमाचल प्रदेश को हरित ऊर्जा राज्य के रूप में परिवर्तित करने की दिशा में प्रदेश की प्रतिबद्धता से भी अवगत करवाया।

जय राम ठाकुर ने राज्य में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश सरकार के प्रयासों की भी जानकारी दी और कहा कि राज्य में 1.70 लाख से अधिक किसान प्राकृतिक खेती अभियान से जुड़े हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने वर्तमान वित्त वर्ष के दौरान प्रदेश में लगभग 50,000 एकड़ भूमि को प्राकृतिक खेती के तहत लाने और सभी 3615 ग्राम पंचायतों में प्राकृतिक खेती का एक मॉडल विकसित करने का भी लक्ष्य निर्धारित किया है।

मुख्यमंत्री ने राज्य के लिए बल्क ड्रग पार्क को स्वीकृति प्रदान करने का भी आग्रह किया, जो न केवल निवेश आकर्षित करेगा बल्कि इससे स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे।

उन्होंने प्रस्तावित नौ राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए अधिसूचना जारी करने के लिए आवश्यक दिशा – निर्देश जारी करने का भी आग्रह किया।

बैठक में नीति आयोग के सदस्य डॉ. वी.के. पॉल, आवासीय आयुक्त मीरा मोहंती और नीति आयोग के अधिकारी भी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री ने प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति चुनने पर श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को बधाई दी

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने एनडीए की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति निर्वाचित होने पर बधाई दी है।

मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों की ओर से राष्ट्रपति चुने जाने पर उन्हें बधाई देते हुए कहा कि उन्होंने आदिवासी पृष्ठभूमि से सम्बन्धित तथा भारत की सबसे कम उम्र की महिला राष्ट्रपति बन कर इतिहास रच दिया है।

जय राम ठाकुर ने आशा व्यक्त की कि श्रीमती द्रौपदी मुर्मू अपनी दूरदर्शी सोच और अनुभव से भारतीय संविधान के संरक्षक के रूप में उत्कृष्ट कार्य करेंगी।

शिमला शहर के लिए 492 करोड़ रुपये की 24 घंटे जलापूर्ति परियोजना स्वीकृत

शिमला/शैल। शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने जानकारी दी कि भारत सरकार के केन्द्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय के केन्द्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य और पर्यावरण इंजीनियरिंग संगठन के तकनीकी विंग ने शिमला नगर निगम क्षेत्र के अन्तर्गत जलापूर्ति सेवाओं में सुधार के लिए 492 करोड रुपये की सप्ताह भर 24 घंटे जलापूर्ति परियोजना को स्वीकृति प्रदान की है।

उन्होंने कहा कि शिमला जलापूर्ति एवं सीवरेज सेवा वितरण कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रेटर शिमला में जलापूर्ति योजनाओं के सुधार के लिए 1825 करोड़ रुपये वित्तीय परिव्यय की परियोजना को विश्व बैंक द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। उन्होंने कहा कि 1825 करोड़ रुपये की इस परियोजना में विश्व बैंक द्वारा 1168 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी तथा शेष 657 करोड़ रुपये हिमाचल सरकार द्वारा वहन किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि शिमला शहर के लिए सप्ताह भर 24 घंटे जल उपलब्ध करवाने वाली जलापूर्ति परियोजना का मुख्य उद्देश्य नोन रेवेन्यू जल को कम करना, ऊर्जा कुशल प्रौद्योगिकी की शुरुआत, जलापूर्ति प्रणालियों को डिजिटल स्वरूप प्रदान करना और भारत सरकार तथा हिमाचल सरकार के मापदंडों के अनुसार गुणवत्तापूर्ण पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करना है।

उन्होंने कहा कि इस परियोजना के लिए निविदा प्रक्रिया शुरू की गई है तथा 31 अक्तूबर, 2022 तक सफल बोलीकर्त्ता को निविदा देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। यह परियोजना वर्ष 2025 तक पूरी कर ली जाएगी तथा शिमला शहर के नागरिकों को सप्ताह भर 24 घंटे जलापूर्ति सुनिश्चित होगी।

हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय का 53वां स्थापना दिवस आयोजित

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला के 53वें स्थापना दिवस के अवसर पर विश्वविद्यालय परिसर में गरिमापूर्ण समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर मुख्यातिथि राज्यपाल राजेन्द्र विश्वनाथ आर्लेकर के साथ शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज और शिक्षा मंत्री गोविन्द सिंह ठाकुर भी उपस्थित थे।

राज्यपाल ने प्रदेश विश्वविद्यालय के अध्यापकों और विद्यार्थियों को स्थापना दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि शिक्षा का मुख्य ध्येय व्यक्ति को संस्कारवान बनाना है। उन्होंने कहा कि पाठय पुस्तकों के अलावा अच्छी किताबें पढ़ने से ही हमारा सर्वांगीण विकास सम्भव है। उन्होंने कहा कि बदलते दौर में हमें अपनी सोच में भी परिवर्तन लाने की आवश्यकता है। शिक्षा को हमें उद्यमिता की ओर ले जाना चाहिए और विश्वविद्यालयों को इस दिशा में कार्य करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों का पाठयक्रम समाज की वर्तमान आवश्यकताओं के अनुरूप होना चाहिए। उन्होंने कहा कि पहले शैक्षणिक पाठयक्रम रोजगार के अनुरूप बनाया जाता था परन्तु वर्तमान में इसका समाज की आवश्यकताओं के अनुरूप होना अधिक महत्वपूर्ण है।

राज्यपाल ने कहा कि 53 वर्षों की इस यात्रा में हमें सफलताओं और कमियों

के बारे में विश्लेषण करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि आज विद्यार्थी किसी भी संस्थान में दाखिला लेने से पहले उसकी ग्रेडिंग के सम्बंध में जानकारी प्राप्त करता है इसलिए विश्वविद्यालय को ग्रेडिंग सुधारने के लिए विशेष प्रयास करने चाहिए।

राज्यपाल ने इस अवसर पर छात्राओं के लिए 8.11 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित होने वाले मणीकर्ण छात्रा छात्रावास का शिलान्यास भी किया। इस छात्रावास का निर्माण भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना के अंतर्गत 4410 वर्ग मीटर में किया जाएगा।

उन्होंने इस अवसर पर मॉय यूनिवर्सिटी थीम पर आधारित चित्रकला कार्यशाला का शुभारम्भ भी किया।

राज्यपाल ने इस अवसर पर हिमशिखर, नवोन्मेषी और विश्वविद्यालय के अन्य प्रकाशनों का भी विमोचन किया। राज्यपाल ने इस अवसर पर श्रेष्ठ छात्र सम्मान, श्रेष्ठ कर्मचारी सम्मान, बेस्ट यंग रिसर्चर अवार्ड, बेस्ट रिसर्चर अवार्ड, बेस्ट टीचर अवार्ड भी प्रदान किए।

उन्होंने इस अवसर प्रो. चन्द्र मोहन परशेरा को विश्वविद्यालय के आन्तरिक गुणवत्ता सुधार में योगदान के लिए सम्मानित किया।

सड़क सुरक्षा कार्यक्रम बनाने, समन्वय और निगरानी के लिए डीआरएससी का गठन

शिमला/शैल। राज्य सरकार ने सभी जिलों में सड़क सुरक्षा कार्यक्रम बनाने, समन्वय करने और निगरानी करने के लिए जिला सड़क सुरक्षा समिति (डीआरएससी) का गठन किया है। उपायुक्त एवं जिला दण्डाधिकारी (पदेन) की अध्यक्षता वाली समिति राज्य सड़क सुरक्षा नीति के क्रियान्वयन एवं इसके अन्तर्गत निर्धारित लक्ष्यों की निगरानी करेगी। यह नियमित रूप से राज्य सड़क सुरक्षा परिषद (एसआरएससी) को जिले में हुई सड़क दुर्घटनाओं के विवरण पर अपडेट करेगी, जिसमें वाहन का विवरण, दुर्घटना का कारण, मौके की जांच का विवरण, सबूत, अपराधी और पीड़ितों का विवरण और उनकी नवीनतम स्थिति, चोट का प्रकार और प्राथमिकी रिपोर्ट दर्ज करना आदि शामिल है।

यह समिति सड़क दुर्घटना पीड़ितों की सहायता के लिए नेक व्यक्ति (गुड सेमेरिटिन) की अवधारणा को बढ़ावा देगी। डीआरएससी जिला वेबसाइट पोर्टल और केन्द्रीय सड़क परिवहन और एवं राजमार्ग मंत्रालय के पोर्टल (http://morth-roadsafety .nic.in /edisha / ndex-aspx) के सार्वजनिक डोमेन पर मासिक आधार पर सड़क दुर्घटनाओं का डेटा प्रकाशित करेगी।

समिति जिला सड़क सुरक्षा योजना विकसित करेगी और जिलों में बड़े स्तर पर होने वाली दुर्घटनाओं से बचाव के लिए एक आपातकालीन चिकित्सा योजना तैयार करेगी। यह बड़े स्तर पर होने वाली दुर्घटनाओं की फोरेंसिक जांच सुनिश्चित करेगी और पूर्व के केस लोड के अनुसार विभिन्न एम्बुलेंस की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करेगी और इन एम्बुलेंसों के प्लेसमेंट को प्रतिक्रिया समय में सुधार करने और अस्पतालों को समय पर सौंपने में मदद करेगी। समिति द्वारा पूर्व सूचना प्रणाली स्थापित करके तथा आपात स्थिति में बिस्तरों की उपलब्धता का पता लगाने के लिए अस्पतालों और एम्बुलेंस के बीच संपर्क भी सुनिश्चित किया जाएगा।

डीआरएससी, आवश्यकताओं और सड़क सुरक्षा निधि में वितरण के लिए नोडल निकाय के रूप में कार्य करेगी तथा महत्वपूर्ण मामलों पर एसआरएससी के साथ संवाद भी स्थापित करेगी। यह राज्य की एसआरएससी/प्रमुख एजेंसी को नियमित रूप से जानकारी और सड़क सुरक्षा उपायों, विशेष रूप से प्रमुख दुर्घटना संभावित क्षेत्रों, ब्लैक स्पॉट आदि की पहचान के संबंध में 4ई यानि इंजीनियरिंग, शिक्षा, प्रवर्तन और आपातकाल की सिफारिश करेगी। समिति राज्य सरकार को विभिन्न नियम और योजनाएं बनाने या उनमें संशोधन करने के लिए सुझाव भी देगी। डीआरएससी वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर कम से कम 15 दिन में एक बार अपनी बैठक आयोजित करेगी और महीने में कम से कम एक बार परोक्ष रूप से बैठक करेगी तथा विभिन्न गतिविधियों पर समय – समय पर विस्तृत रिपोर्ट भेजेगी।

पुलिस अधीक्षक, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, लोक निर्माण विभाग के अधिशाषी अभियंता, सड़क, परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के क्षेत्रीय अधिकारी के प्रतिनिधि, एनएचएआई के परियोजना निदेशक, नगर निगम, शहरी निकाय और अधिसूचित प्राधिकरण के कार्यकारी अधिकारी, सड़क सुरक्षा में सुधार के लिए कार्यरत कम से कम एक सिविल सोसाइटी संगठन या कोई अन्य गैर सरकारी संगठन तथा क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी समिति के सदस्य होंगे और राज्य राजमार्गों और प्रमुख जिला सड़कों (एमडीआर) के राजमार्ग प्रशासक सदस्य सचिव के रूप में कार्य करेंगे।

दूरसंचार कनेक्टिविटी के विस्तार में तेजी लाने के निर्देश:मुख्य सचिव

शिमला/शैल। मुख्य सचिव आर.डी. धीमान की अध्यक्षता में भारत सरकार के राष्ट्रीय ब्राडबैंड मिशन, ब्राडबैंड फॉर ऑल, के दृष्टिगत गठित राज्य ब्रॉडबैंड कमेटी की बैठक आयोजित की गई।

उन्होंने राष्ट्रीय ब्राडबैंड मिशन के तहत प्रदेश भर में उच्च गति ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी की प्रगति की समीक्षा की और राज्य में दूरसंचार कनेक्टिविटी में तेजी लाने की योजना पर चर्चा भी की।

आर.डी. धीमान ने दूरसंचार विभाग (डीओटी) को असंबद्ध गांवों में दूरसंचार कनेक्टिविटी के विस्तार में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने दूरसंचार विभाग को वाइब्रेंट ग्राम परियोजना के अन्तर्गत किन्नौर व लाहौल – स्पीति जिला के 24 सीमावर्ती गांवों और आकांक्षी जिला परियोजना के अन्तर्गत चंबा के 46 गांवों में मार्च, 2023 तक दूरसंचार कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने प्रदेश में कार्यरत सभी दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के दूरसंचार बुनियादी ढांचे को साझा करने पर भी बल दिया। इससे नागरिकों को गुणवत्ता युक्त सेवाएं उपलब्ध करवाने में मदद मिलेगी और दूरसंचार बुनियादी ढांचे, विशेष रूप से कस्बों में अव्यवस्था कम होगी। मुख्य सचिव ने आश्वस्त किया कि राज्य द्वारा राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड मिशन के कार्यान्वयन में भारत सरकार के दूरसंचार विभाग को हर संभव सहायता प्रदान की जाएगी।

भारतीय दूरसंचार विभाग ने राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड मिशन के तहत निर्धारित लक्ष्य की स्थिति को साझा करते हुए बताया कि राज्य के 96.20 प्रतिशत गांवों में 9 एमबीपीएस से 12.4 एमबीपीएस तक की ब्रॉडबैंड स्पीड के साथ ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान की जा रही है। राज्य में अभी भी 585 ऐसे गांव हैं जो ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी से जुड़े नहीं हैं या इन्हें आंशिक तौर पर कवर किया गया है। इस बैठक में दूरसंचार विभाग, भारतीय दूरसंचार निगम लिमिटेड, डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर एसोसिएशन, सेलुलर ऑपरेटर्ज एसोसिएशन ऑफ इण्डिया और प्रदेश सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी, लोक निर्माण विभाग, शहरी विकास, बहुउद्देशीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा विभाग के प्रतिनिधि उपस्थित थे।

शिक्षा का अर्थ है उस पूर्णता को व्यक्त करना जो सब मनुष्यों में पहले से विद्यमान है।
.....स्वामी विवेकानंद

सम्पादकीय

महामहिम द्रौपदी मुर्मू और कुछ संभावित सवाल

राष्ट्रपति देश का संविधान प्रदत्त सर्वोच्च पद है। पन्द्रहवें राष्ट्रपति के रूप में द्रौपदी मुर्मू इस पद के लिए निर्वाचित हुई हैं। उनकी जीत सुनिश्चित थी क्योंकि वह एन.डी.ए. की उम्मीदवार थी। केन्द्र में पिछले आठ वर्षो से एन.डी.ए. की सरकार है और अठारह राज्यों में भी भाजपा या एन.डी.ए. की सरकारें हैं। इस गणित को सामने रखते हुये यह सोचना/मानना भी अपने आप को ही झुटलाने जैसा होता कि इसके परिणाम कुछ भिन्न भी हो सकते थे। इसलिये इस जीत के लिये जहां आदिवासी महिला द्रौपदी मुर्मू बधाई की पात्र हैं वहीं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसका श्रेय जाता है जिन्होंने मर्मू को उम्मीदवार बनाया। द्रौपदी मुर्मू की जीत जितनी सुनिश्चित थी उसी अनुपात में इस चुनाव में विपक्षी उम्मीदवार यशवन्त सिन्हा ने जितने सवाल देश के सामने उछाले हैं वह शायद इस जीत से भी ज्यादा बड़े हो जाते हैं। यशवन्त सिन्हा पूरे चुनाव प्रचार के दौरान यह सवाल देश के सामने अपनी पत्रकार वार्ताओं के माध्यम से रखते आये हैं जबकि द्रौपदी मुर्मू ने एक बार भी देश के सामने इन सवालों पर अपना मुंह नहीं खोला। भाजपा/एन.डी.ए. में सोचने और बोलने का अधिकार केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ही पास है और मुर्मू ने भी इस प्रथा का ईमानदारी से निर्वहन किया है।

द्रौपदी मुर्मू देश की पन्द्रहवीं राष्ट्रपति बनी है। आजाद भारत में पैदा हुई और आदिवासी समाज से आने वाली मुर्मू का प्रारम्भिक जीवन बहुत संघर्षपूर्ण रहा है। पति और बेटों की मौत के बाद एक लिपिक के रूप में अपना जीवन शुरू करके शिक्षक बनी और वहीं से राजनीतिक शुरुआत करके इस पद तक पहुंची हैं। यह आदिवासी होना ही इस चयन का आधार बना है। क्योंकि देश में 10 करोड़ आदिवासी हैं और बहुत सारे राज्यों में जीत का गणित आदिवासियों के पास है। इसी गणित के कारण झारखण्ड सरकार ने राजनीति में कांग्रेस के साथ होने के बावजूद राष्ट्रपति के लिए आदिवासी मुर्मू को अपना समर्थन दिया। पश्चिम बंगाल में भी करीब सात प्रतिशत आदिवासी हैं इसी के कारण ममता को यह बयान देना पड़ा था कि यदि एन.डी.ए. ने मुर्मू की पूर्व जानकारी दे दी होती तो टी.एम.सी. भी द्रौपदी मुर्मू का समर्थन कर देती। पिछली बार जब एन.डी.ए. ने रामनाथ कोविन्द को उम्मीदवार बनाया था तब दलित वर्ग से ताल्लुक रखने का तर्क दिया गया था। इस तरह के तर्कों से यह स्पष्ट हो जाता है कि अब राष्ट्रपति जैसे सर्वोच्च पद के लिये भी संविधान की विशेषज्ञता जैसी अपेक्षाओं की उम्मीद करना असंभव होगा। जिस दल के पास सत्ता होगी अब राष्ट्रपति भी उसी दल की विचारधारा के प्रति प्रतिबद्ध एक बड़ा कार्यकर्ता होगा। दल के नेता के प्रति निष्ठा ही चयन का आधार होगी।

इस समय देश की आर्थिक स्थिति बहुत ही संकट से गुजर रही है। सरकार को साधारण खाद्य सामग्री पर भी जीएसटी लगाना पड़ गया है। रुपये की डॉलर के मुकाबले गिरावट लगातार जारी है। संसद में महंगाई और बेरोजगारी पर लगातार हंगामा हो रहा है। राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ जांच एजेंसियों का इस्तेमाल अब आम आदमी में भी चर्चा का विषय बनता जा रहा है। सत्तारूढ़ भाजपा मुस्लिम मुक्त हो चुकी है। संसद से लेकर राज्यों की विधानसभाओं तक भाजपा में एक भी मुस्लिम सदस्य नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय के जजों तक को सोशल मीडिया में निशाना बनाया जा रहा है। नई शिक्षा नीति में मनुस्मृति को पाठयक्रम का हिस्सा बनाने की बात हो रही है। इस परिदृश्य में भी सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास के दावे किये जा रहे हैं। यशवंत सिन्हा लगातार यह सवाल जनता के सामने रख रहे थे और द्रौपदी मुर्मू लगातार चुप्पी साधे चल रही थी। आदिवासी समाज के सौ से अधिक लोग कैसे बिना कसूर के पांच वर्ष जेल में रहे हैं यह सच भी सामने आ गया है। ऐसे में आने वाले दिनों में यह देखना दिलचस्प होगा कि बाबासाहेब अंबेडकर के संविधान की रक्षा मुख्य मुद्दा बनेगी या मनुस्मृति को पाठयक्रम का हिस्सा बनाना।

नीति आयोग ने डिजिटल बैंक पर रिपोर्ट जारी की, भारत के लिए एक लाइसेंसिंग एवं नियामकीय व्यवस्था का प्रस्ताव दिया

शिमला। नीति आयोग की रिपोर्ट डिजिटल बैंकों के लिए एक लाइसेंसिंग एवं नियामकीय व्यवस्था के लिए खाका और रूपरेखा प्रस्तुत करती है। यह किसी भी नियामकीय अथवा नीतिगत मध्यस्थता को नजरअंदाज करने पर ध्यान केंद्रित करते हुए मौजूदा के साथ-साथ प्रतिस्पर्धियों के लिए समान अवसर उपलब्ध कराती है।

नीति आयोग के चेयरमैन सुमन बेरी, सीईओ परमेश्वरन अय्यर एवं वरिष्ठ सलाहकार अन्ना रॉय ने अन्य अधिकारियों की उपस्थिति में यह रिपोर्ट जारी की।

सीईओ परमेश्वरन अय्यर ने कहा, 'भारत में बैंकिंग जरूरतों को पूरा करने के लिए प्रभावी तौर पर प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने की आवश्यकता को देखते हुए यह रिपोर्ट मौजूदा कमियों, बैंकिंग सेवाओं की पहुंच से छूटे हुए स्थानों और डिजिटल बैंकों की लाइसेंसिंग में सर्वोत्तम वैश्विक नियामकीय प्रथाओं का अध्ययन करती है।

सिफारिश की मुख्य बातें:

इस रिपोर्ट में निम्नलिखित चरणों को शामिल करते हुए सावधानीपूर्वक कैलिब्रेटेड दृष्टिकोण की सिफारिश की गई है।

1. प्रतिबंधित डिजिटल बैंक लाइसेंस (आवेदक को) जारी करना (ग्राहकों को दी गई सेवाओं की मात्रा/मूल्य और लाइक के संदर्भ में यह लाइसेंस प्रतिबंधित होगा)।

2. भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अधिनियमित एक नियामकीय सैंडबॉक्स ढांचे में (लाइसेंसधारी का) नामांकन।

3. 'फुल-स्केल' डिजिटल बैंक लाइसेंस जारी करना (विशेषता, विवेकपूर्ण और तकनीकी जोखिम प्रबंधन सहित नियामक सैंडबॉक्स में लाइसेंसधारी के संतोषजनक प्रदर्शन पर निर्भर)।

यह रिपोर्ट इस क्षेत्र में प्रचलित व्यापार म डलों को भी मैप करती है और नियो-बैंकिंग के 'साझेदारी मॉडल' की चुनौतियों पर प्रकाश डालती है। भारत में नियामकीय एवं डिजिटल बैंक लाइसेंस के अभाव में नियो-बैंकिंग तेजी से उभर रही है।

आयोग की इस रिपोर्ट में प्रस्तावित लाइसेंसिंग एवं नियामक रूपरेखा के लिए कार्यप्रणाली समान रूप से भारित 'डिजिटल बैंक नियामकीय सूचकांक' पर आधारित है। इसमें चार कारक शामिल हैं- (i) प्रवेश संबंधी बाधाएं, (ii) प्रतिस्पर्धा, (iii) व्यापार प्रतिबंध और (iv) तकनीकी तटस्थता। इन चार कारकों के तत्वों को सिंगापुर, हांगकांग, ब्रिटेन, मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण कोरिया के पांच बेंचमार्क अधिकार क्षेत्र के खिलाफ मैप किया गया है।

भारत में डिजिटल बैंक के लिए संदर्भः वित्तीय समावेशन

हाल के वर्षो में भारत ने वित्तीय समावेशन को आगे बढ़ाने में तेजी से प्रगति की है और वह प्रधानमंत्री जन धन योजना एवं इंडिया स्टैक से उत्प्रेरित है। हालांकि ऋण तक पहुंच अभी भी एक नीतिगत चुनौती बनी हुई है, विशेष रूप से देश के उन 6.3 करोड़ एमएसएमई के लिए जो जीडीपी में 30 प्रतिशत, विनिर्माण में 45 प्रतिशत और निर्यात में 40 प्रतिशत का योगदान करते हैं। साथ ही वे एक बड़ी आबादी के लिए रोजगार भी सृजित करते हैं।

पिछले कुछ वर्षो के दौरान जन धन-आधार-मोबाइल (जेएएम) और आधार द्वारा शुरू किए गए डिजिटलीकरण के कारण वित्तीय समावेशन भारतीयों के लिए एक वास्तविकता बन गया है। इसे केवल यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई) द्वारा आगे बढ़ाया गया है जिसे लोगों ने असाधारण तौर पर अपनाया है। यूपीआई ने अक्तूबर 2021 में 7.7 लाख करोड़ रुपये के 4.2 अरब से अधिक लेनदेन दर्ज किए। यूपीआई की परिकल्पना के दौरान सरकार द्वारा अपनाए गए प्लेटफॉर्म संबंधी दृष्टिकोण के कारण मूल्यवान भुगतान उत्पादों को इसके आधार पर विकसित किया गया है। परिणामस्वरूप भुगतान अब न केवल खुदरा दुकानों पर महज एक ही क्लिक में बल्कि पीयर टु पीयर भी किया जा सकता है जो लोगों के बीच रकम हस्तांतरण के तरीके को पूरी तरह नए सिरे से परिभाषित करता है।

वित्तीय समावेशन के लिए 'संपूर्ण भारत के दृष्टिकोण' के परिणामस्वरूप पीएम-किसान जैसे ऐप के जरिये प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण और पीएम-स्वनिधि के जरिये गली के फेरेवालों को माइक्रोक्रेडिट सुविधाएं भी प्रदान की जा रही हैं।

भारत ने भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अधिनियमित अकाउंट एग्रीगेटर (एए) नियामकीय ढांचे के जरिये 'ओपन बैंकिंग' के अपने संस्करण को संचालित करने की दिशा में भी कदम उठाए हैं। व्यावसायिक तौर पर तैनाती के बाद एए ढांचे की परिकल्पना उन समूहों के बीच ऋण सुविधाओं को बढ़ाने के लिए की गई है जो अब तक इन सेवाओं की पहुंच से दूर हैं।

भुगतान के मोर्चे पर भारत ने जो सफलता दर्ज की है उसे सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यमों की ऋण संबंधी जरूरतों को पूरा करने के मोर्चे पर दोहराया जाना अभी बाकी है। मौजूदा क्रेडिट गैप और व्यापार एवं नीतिगत बाधाओं से पता चलता है कि इन जरूरतों को पूरा करने के लिए प्रौद्योगिकी का प्रभावी तौर पर लाभ उठाने की आवश्यकता है। साथ ही इन सेवाओं की पहुंच से दूर रहने वालों को औपचारिक वित्तीय दायरे में लाने की आवश्यकता है।

यह रिपोर्ट नीति आयोग द्वारा अंतर-मंत्रालयी परामर्श के आधार पर तैयार की गई है। पिछले साल नीति आयोग ने हितधारकों के साथ व्यापक परामर्श के लिए इस विषय पर एक परिचर्चा पत्र जारी किया था। उसके बाद 24 संगठनों से प्राप्त टिप्पणियों की जांच की गई और उन्हें अंतिम रिपोर्ट में उपयुक्त जगह दी गई है।

वित्तीय सेवा विभाग के अतिरिक्त सचिव सुचिंद्र मिश्रा, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव अमित अग्रवाल, एमएसएमई सहायक विकास आयुक्त ड . ईशिता गांगुली त्रिपाठी और भारतीय बैंक संघ के चेयरमैन अतुल कुमार गोयल भी आज के लॉन्च के दौरान उपस्थित थे।

महिलाओं के लिए लैंगिक समानता सुनिश्चित करने में जेंडर बजट स्टेटमेंट की महत्वपूर्ण भूमिका

शिमला। हिमाचल प्रदेश ने महिलाओं के सामाजिक और आर्थिक उत्थान में उल्लेखनीय प्रगति की है। हिमाचल लैंगिक समानता में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला देश का अग्रणी राज्य बना है। राज्य सरकार लैंगिक समानता सुनिश्चित करने पर विशेष बल दे रही है ताकि प्रदेश की महिलाएं सशक्त और आत्मनिर्भर बन सकें। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए राज्य सरकार ने वित्त वर्ष 2022-23 के बजट में जेंडर बजट स्टेटमेंट का प्रावधान किया है।

राज्य सरकार ने जेंडर बजट स्टेटमेंट के सफल क्रियान्वयन द्वारा महिलाओं के लिए लैंगिक समानता सुनिश्चित कर प्रदेश में महिलाओं के उत्थान के लिए अनेक प्रयास किए हैं। जेंडर बजट स्टेटमेंट, जेंडर रिस्पोंस बजट का एक प्रावधान है, जिसका उद्देश्य विभिन्न संसाधनों का समान लैंगिक वितरण सुनिश्चित करना है, साथ ही जेंडर बजट स्टेटमेंट के प्रभावी क्रियान्वयन के माध्यम से महिलाओं के लिए क्रियान्वित की जा रही नीतियों, कार्यक्रमों और योजनाओं के प्रभाव का विश्लेषण करना है। जेंडर बजट स्टेटमेंट लैंगिक समानता सुनिश्चित करने के साथ महिलाओं के कल्याण व उत्थान के लिए बजट संसाधनों का श्रेष्ठतम उपयोग सुनिश्चित करेगा तथा जेंडर आधारित बजट के प्रभाव का मूल्याकंन भी करेगा।

जेंडर बजटिंग लैंगिक असमानता को कम करने और सभी को एक समान अवसर प्रदान करने में सहायक सिद्ध हो रहा है। लैंगिक असमानता को कम करने के लिए हर विभाग की भागीदारी महत्त्वपूर्ण है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए विभिन्न विभागों में जेंडर बजट सैल गठित किए गए हैं। जेंडर बजट सैल एक संस्थागत प्रणाली है जो सरकारी बजट में जेंडर विश्लेषण के एकीकरण की सुविधा प्रदान करती है।

विभागों द्वारा स्थापित किए गए जेंडर बजट सैल के मार्गदर्शन के लिए प्रदेश सरकार हिमाचल प्रदेश लोक प्रशासन संस्थान, राज्य महिला एवं बाल विकास विभाग और संयुक्त राष्ट्र महिला भारत, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार के संयुक्त तत्वाधान से कार्यशालाओं और प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। प्रदेश के हितधारकों की सहायता के लिए कार्यशालाएं, प्रशिक्षण मॉडयूल, सूचना पुस्तिकाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं ताकि विभागों द्वारा जेंडर बजट स्टेटमेंट का सफल क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जा सके।

प्रदेश सरकार द्वारा जेंडर बजट स्टेटमेंट का सफल क्रियान्वयन सुनिश्चित कर महिलाओं और लड़कियों के विकास के उत्थान के लिए आवश्यक धनराशि उपलब्ध करवाई गई है। जेंडर बजट स्टेटमेंट के माध्यम से विभिन्न विभागों के वित्तीय प्रदर्शन की निगरानी तथा धनराशि का योजनानुसार उपयोग का आकलन भी किया जा रहा है। इसके माध्यम से लैंगिक संवेदनशील नीतियों और कार्यक्रमों के प्रभावी कार्यान्वयन में बजट आबंटन व उपलब्धता का आकलन करने और प्रदेश में लैंगिक समानता की स्थिति को बढ़ाने में भी सहायता मिल रही है।

भारत के राष्ट्रपति राम नाथ कोविन्द का राष्ट्र के नाम विदाई संदेश

आज से पांच साल पहले, आप सबने मुझ पर अपार भरोसा जताया था और अपने निर्वाचित जन-प्रतिनिधियों के माध्यम से मुझे भारत के राष्ट्रपति के रूप में चुना था। आज मेरा कार्यकाल पूरा हो रहा है। इस अवसर पर मैं आप सभी के साथ कुछ बातें साझा करना चाहता हूं।

सबसे पहले, मैं आप सभी देशवासियों के प्रति तथा आपके जन-प्रतिनिधियों के प्रति हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। पूरे देश में अपनी यात्राओं के दौरान, नागरिकों के साथ हुए संवाद और संपर्क से मुझे निरंतर प्रेरणा मिलती रही। छोटे-छोटे गांवों में रहने वाले हमारे किसान और मजदूर भाई-बहन, नई पीढ़ी के जीवन को संवारने वाले हमारे शिक्षक, हमारी विरासत को समृद्ध बनाने वाले कलाकार, हमारे देश के विभिन्न आयामों का अध्ययन करने वाले विद्वान, देश की समृद्धि बढ़ाने वाले उद्यमी, देशवासियों की सेवा करने वाले डॉक्टर व नर्स, राष्ट्र-निर्माण में संलग्न वैज्ञानिक व इंजीनियर, देश की न्याय व्यवस्था को योगदान देने वाले न्यायाधीश व अधिवक्ता, प्रशासन तंत्र को सुचारु रूप से चलाने वाले सिविल सर्वेंट्स, हर वर्ग को विकास से जोड़ने में सक्रिय हमारे सामाजिक कार्यकर्ता, भारतीय समाज में आध्यात्मिक प्रवाह को बनाए रखने वाले सभी पंथों के आचार्य व गुरुजन आप सभी ने मुझे अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में भरपूर सहयोग दिया है। संक्षेप में कहूं तो समाज के सभी वर्गों का मुझे पूरा सहयोग, समर्थन व आशीर्वाद मिला है।

मेरे मनो-मस्तिष्क में वे सभी क्षण विशेष रूप से अंकित रहेंगे जब मेरी मुलाक़ात अपनी सेनाओं, अर्धसैनिक बलों, तथा पुलिस के बहादुर जवानों से होती थी। उन सभी में देशप्रेम की अद्भुत भावना देखने को मिलती है। अपनी विदेश यात्राओं के दौरान, जब भी प्रवासी भारतीयों के साथ मेरा मिलना हुआ, हर बार मुझे मातृभूमि के प्रति उनके गहरे प्यार और अपनेपन का एहसास हुआ। देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार समारोहों के दौरान, मुझे अनेक असाधारण प्रतिभाओं से मिलने का अवसर मिला। वे सभी पूरी लगन, अटूट समर्पण और दृढ़ निष्ठा के साथ एक बेहतर भारत के निर्माण में सक्रिय हैं।

इस प्रकार, अनेक देशवासियों से मिलने के बाद मेरा यह विश्वास और भी दृढ़ हुआ कि हमारे निष्ठावान नागरिक ही वास्तविक राष्ट्र-निर्माता हैं। और वे सभी भारत को बेहतर बनाने के लिए प्रयासरत हैं। ऐसे सभी निष्ठावान देशवासियों के हाथों में हमारे महान देश का भविष्य सुरक्षित है।

अपने इन अनुभवों से गुजरते हुए अक्सर मुझे अपना बचपन भी याद आता रहा है कि किस तरह महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाएं हमारे व्यक्तिगत जीवन को प्रभावित करती रहीं।

जब अपने छोटे से गांव में, एक साधारण बालक के नजरिए से मैं जीवन को समझने की कोशिश कर रहा था, तब देश को आजादी हासिल किए हुए कुछ ही साल हुए थे। देश के पुनर्निर्माण के लिए लोगों में एक नया जोश दिखाई देता था (उनकी आंखों में नए सपने थे। मेरे दिलो-दिमाग में भी एक धुंधली सी कल्पना उभर रही थी कि एक दिन शायद मैं भी अपने देश के निर्माण में भागीदारी कर सकूंगा। कच्चे घर में गुजर-बसर करने वाले एक परिवार के मेरे जैसे साधारण बालक के लिए हमारे गणतंत्र के सर्वोच्च संवैधानिक पद के बारे में कोई भी जानकारी होना कल्पना से परे था। लेकिन यह भारत के लोकतंत्र की ताकत है कि इसमें हर नागरिक के लिए ऐसे रास्ते खुले हैं जिनपर चलकर वह देश की नियति को संवारने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। कानपुर देहात जिले के परौंख गांव के अति साधारण परिवार में पला-बढ़ा वह राम नाथ कोविन्द आज आप सभी देशवासियों को संबोधित कर रहा है, इसके लिए मैं अपने देश की जीवंत लोकतांत्रिक व्यवस्था की शक्ति को शत-शत नमन करता हूं।

चूंकि मैंने अपने गांव का उल्लेख किया है, तो मैं इस बात का भी उल्लेख करना चाहूंगा कि राष्ट्रपति के कार्यकाल के दौरान अपने पैतृक गांव का दौरा करना और अपने कानपुर के विद्यालय में वयोवृद्ध शिक्षकों के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लेना मेरे जीवन के सबसे यादगार पलों में हमेशा शामिल रहेंगे। इसी साल प्रधानमंत्री जी भी मेरे गाँव परौंख आए और उन्होंने मेरे गांव की धरती का मान बढ़ाया। अपनी जड़ों से जुड़े रहना भारतीय संस्कृति की विशेषता है। मैं युवा पीढ़ी से यह अनुरोध करूंगा कि अपने गाँव या नगर तथा अपने विद्यालयों तथा शिक्षकों से जुड़े रहने की इस परंपरा को आगे बढ़ाते रहें।

आजकल सभी देशवासी 'आजादी का अमृत महोत्सव' मना रहे हैं। अगले महीने हम सब भारत की आजादी की 75वीं वर्षगांठ मनाएंगे। हम 25 वर्ष की अवधि के उस 'अमृत काल' में प्रवेश करेंगे, जो स्वतंत्रता के शताब्दी वर्ष अर्थात 2047 में पूरा होगा। ये विशेष ऐतिहासिक वर्ष हमारे गणतंत्र के प्रगति-पथ पर मील के पत्थर की तरह हैं। हमारे लोकतन्त्र की यह विकास यात्रा, देश की स्वर्णिम संभावनाओं को कार्यरूप देकर विश्व समुदाय के समक्ष एक श्रेष्ठ भारत को प्रस्तुत करने की यात्रा है।

आधुनिक काल में, हमारे देश की इस गौरव यात्रा का आरंभ ब्रिटिश हुकूमत के दौरान राष्ट्रवादी भावनाओं के जागरण और स्वाधीनता संग्राम के साथ हुआ। उन्नीसवीं शताब्दी के दौरान पूरे देश में पराधीनता के विरुद्ध अनेक विद्रोह हुए। देशवासियों में नयी आशा का संचार करने वाले ऐसे विद्रोहों के अधिकांश नायकों के नाम भुला दिए गए थे। अब उनकी वीर-गाथाओं को आदर सहित याद किया जा रहा है। उन्नीसवीं सदी के अंतिम तथा बीसवीं सदी के आरंभिक वर्षों में नवीन जन-चेतनाओं का संचार हो रहा था और स्वाधीनता संग्राम की अनेक धाराएँ प्रवाहित हो रही थीं।

वर्ष 1915 में जब गांधीजी स्वदेश लौटे, उस समय देश में राष्ट्रीयता की भावना और भी प्रबल हो रही थी। अनेक महान जननायकों की उज्ज्वल आकाश-गंगा का जैसा प्रकाश हमारे देश को बीसवीं सदी के आरंभिक दशकों में प्राप्त हुआ, वह विश्व इतिहास में अतुलनीय है। जहां एक ओर आधुनिक युग के एक 'ऋषि' की तरह, गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर, हमारी सांस्कृतिक विरासत से देशवासियों को फिर से जोड़ रहे थे, वहीं दूसरी ओर बाबासाहब भीमराव आम्बेडकर समानता के आदर्श की ऐसी पुरजोर वकालत कर रहे थे जैसा अधिकांश विकसित देशों में भी दिखाई नहीं दे रहा था। तिलक और गोखले से लेकर भगत सिंह और नेताजी सुभाष चन्द्र बोस तक (जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल और श्यामा प्रसाद मुकर्जी से लेकर सरोजिनी नायडू और कमलादेवी चट्टोपाध्याय तक-ऐसी अनेक विभूतियों का केवल एक ही लक्ष्य के लिए तत्पर होना, मानवता के इतिहास में अन्यत्र नहीं देखा गया है।

मेरे मस्तिष्क में और भी कई विभूतियों के नाम उभर रहे हैं, लेकिन मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि स्वाधीन भारत की विभिन्न परिकल्पनाओं से सम्पन्न अनेक महान नेताओं ने भारत की स्वाधीनता के लिए त्याग और बलिदान के अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत किए। इसमें कोई संदेह नहीं है कि स्वाधीनता संग्राम पर गांधीजी के परिवर्तनकारी विचारों का प्रभाव सबसे अधिक पड़ा और उस दौरान उन्होंने कोटि-कोटि देशवासियों की जीवनधारा को नयी दिशा दे दी।

लोकतन्त्र के जिस पथ पर हम आज आगे बढ़ रहे हैं उसकी रूप-रेखा हमारी संविधान सभा द्वारा तैयार की गयी थी। उस सभा में पूरे देश का प्रतिनिधित्व करने वाले अनेक महानुभावों में हंसाबेन मेहता, दुर्गाबाई देशमुख, राजकुमारी अमृत कौर तथा सुचेता कृपलानी सहित 15 महिलाएं भी शामिल थीं। संविधान सभा के सदस्यों के अमूल्य योगदान से निर्मित भारत का संविधान, हमारा प्रकाश-स्तम्भ रहा है और इसमें निहित आदर्श, चिरकाल से संरक्षित भारतीय जीवन-मूल्यों का हिस्सा रहे हैं।

संविधान को अंगीकृत किए जाने से एक दिन पहले संविधान सभा में अपने समापन वक्तव्य में, डॉक्टर आम्बेडकर ने लोकतंत्र के सामाजिक और राजनीतिक आयामों के बीच के अंतर को स्पष्ट किया था। उन्होंने कहा था कि हमें केवल राजनीतिक लोकतंत्र से संतुष्ट नहीं होना चाहिए। मैं उनके शब्दों को आप सबके साथ साझा करता हूं। उन्होंने कहा था, 'हमें अपने राजनीतिक लोकतंत्र को एक सामाजिक लोकतंत्र भी बनाना चाहिए। राजनीतिक लोकतंत्र टिक नहीं सकता यदि वह सामाजिक लोकतंत्र पर आधारित न हो। सामाजिक लोकतंत्र का क्या अर्थ है? इसका अर्थ है जीवन का वह तरीका जो स्वतंत्रता, समानता और बंधुता को जीवन के सिद्धांतों के रूप में मान्यता देता है। स्वतंत्रता, समानता और बंधुता के इन सिद्धांतों को एक त्रिमूर्ति के अलग-अलग हिस्सों के रूप में नहीं देखना चाहिए। उनकी त्रिमूर्ति का वास्तविक अर्थ यह है कि उनमें से किसी भी हिस्से को एक-दूसरे से अलग करने पर लोकतंत्र का वास्तविक उद्देश्य ही समाप्त हो जाता है।

जीवन-मूल्यों की यह त्रिमूर्ति आदर्श-युक्त, उदारता-पूर्ण और प्रेरणादायक है। इस त्रिमूर्ति को अमूर्त अवधारणा मात्र समझना गलत होगा। केवल आधुनिक ही नहीं बल्कि हमारा प्राचीन इतिहास भी इस बात की गवाही देता है कि वे तीनों जीवन-मूल्य हमारे जीवन की सच्चाई हैं (उन्हें हासिल किया जा सकता है, और वस्तुतः उन्हें विभिन्न युगों में हासिल किया भी गया है। हमारे पूर्वजों और हमारे आधुनिक राष्ट्र-निर्माताओं ने अपने कठिन परिश्रम और सेवा भावना के द्वारा न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुता के आदर्शों को चरितार्थ किया था। हमें केवल उनके पदचिह्नों पर चलना है और आगे बढ़ते रहना है।

सवाल उठता है कि आज के संदर्भ में एक सामान्य नागरिक के लिए ऐसे आदर्शों का क्या अर्थ है? मेरा मानना है कि उन आदर्शों का प्रमुख लक्ष्य सामान्य व्यक्ति के लिए सुखमय जीवन का मार्ग प्रशस्त करना है। इसके लिए, सबसे पहले सामान्य लोगों की मूलभूत आवश्यकताएं पूरी की जानी चाहिए। अब संसाधनों की कमी नहीं है। हर परिवार के पास बेहतर आवास, तथा पीने के पानी और बिजली की सुविधा उपलब्ध हो इस दिशा में हम काम कर रहे हैं। यह बदलाव, विकास की बढ़ती हुई गति तथा भेदभाव से पूर्णतः मुक्त सुशासन द्वारा ही संभव हो सका है।

मूलभूत आवश्यकताओं को उपलब्ध कराने के बाद, यह सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक नागरिक अपनी क्षमताओं का उपयोग करते हुए खुशी के अवसर तलाशे तथा अपने नितांत निजी गुणों का समुचित उपयोग करते हुए अपनी नियति का निर्माण करे। इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए शिक्षा ही मुख्य साधन है। मेरा मानना है कि 'राष्ट्रीय शिक्षा नीति' युवा भारतीयों के लिए अपनी विरासत से जुड़ने और इक्कीसवीं सदी में अपने पैर जमाने में बहुत सहायक सिद्ध होगी। उनके विकासमान भविष्य के लिए अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं अनिवार्य हैं। कोविड की वैश्विक महामारी ने सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा के बुनियादी ढांचे में और अधिक सुधार की आवश्यकता को रेखांकित किया है। मुझे खुशी है कि सरकार ने इस कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठाते हुए हमारे देशवासी सक्षम बन सकते हैं और आर्थिक सुधारों का लाभ लेकर अपने जीवन निर्माण के लिए सर्वोत्तम मार्ग अपना सकते हैं। 21वीं सदी को भारत की सदी बनाने के लिए हमारा देश सक्षम हो रहा है, यह मेरा दृढ़ विश्वास है।

अपने कार्यकाल के पांच वर्षों के दौरान, मैंने अपनी पूरी योग्यता से अपने दायित्वों का निर्वहन किया है। मैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर एस. राधाकृष्णन और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जैसी महान विभूतियों का उत्तराधिकारी होने के नाते बहुत सचेत रहा हूं। जब मैंने राष्ट्रपति भवन में प्रवेश किया था, तब मेरे तत्कालीन पूर्ववर्ती, श्री प्रणब मुखर्जी ने भी मेरे कर्तव्यों के बारे में मुझे बुद्धिमत्तापूर्ण सुझाव दिए। फिर भी, जब कभी मुझे किसी तरह का संशय हुआ, तब मैंने गांधीजी का और उनके द्वारा सुझाए गए मूल-मंत्र का सहारा लिया। गांधीजी की सलाह के मुताबिक सबसे अच्छा मार्गदर्शक-सिद्धान्त यह था कि हम सबसे गरीब आदमी के चेहरे को याद करें और खुद से यह सवाल पूछें कि हम जो कदम उठाने जा रहे हैं, क्या वह उस गरीब के लिए सहायक होगा? मैं गांधीजी के सिद्धांतों पर अपने अटूट विश्वास को दोहराते हुए आप सबसे यह आग्रह करूंगा कि आप प्रतिदिन, कुछ मिनटों के लिए ही सही, गांधीजी के जीवन और शिक्षाओं पर अवश्य विचार करें।

हम सबके लिए माता की तरह पूज्य प्रकृति, गहरी पीड़ा से गुजर रही है। जलवायु परिवर्तन का संकट हमारी धरती के भविष्य के लिए गंभीर खतरा बना हुआ है। हमें अपने बच्चों की खातिर अपने पर्यावरण, अपनी जमीन, हवा और पानी का संरक्षण करना है। अपनी दिनचर्या में तथा रोज़मर्रा की चीजों का इस्तेमाल करते समय हमें अपने पेड़ों, नदियों, समुद्रों और पहाड़ों के साथ-साथ अन्य सभी जीव-जंतुओं की रक्षा के लिए बहुत सावधान रहने की जरूरत है। प्रथम नागरिक के रूप में, यदि अपने देशवासियों को मुझे कोई एक सलाह देनी हो तो मैं यही सलाह दूंगा।

अपने वक्तव्य का समापन करते हुए मैं एक बार फिर सभी देशवासियों के प्रति हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। भारत माता को सादर नमन करते हुए मैं आप सभी के उज्ज्वल भविष्य की मंगल कामना करता हूं।

निर्दलीय विधायकों प्रकाश राणा व होशियार सिंह राणा की सदस्यता रद्द करने की मांग को लेकर याचिका दायर

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश विधान सभा में जोगेन्द्रनगर तथा देहरा के दोनों निर्दलीय विधायकों प्रकाश राणा व होशियार सिंह राणा के भाजपा में शामिल होने के विरोध में नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री की अध्यक्षता में विधानसभा सचिव के कार्यालय में कांग्रेस विधायक दल के सचिव नंद

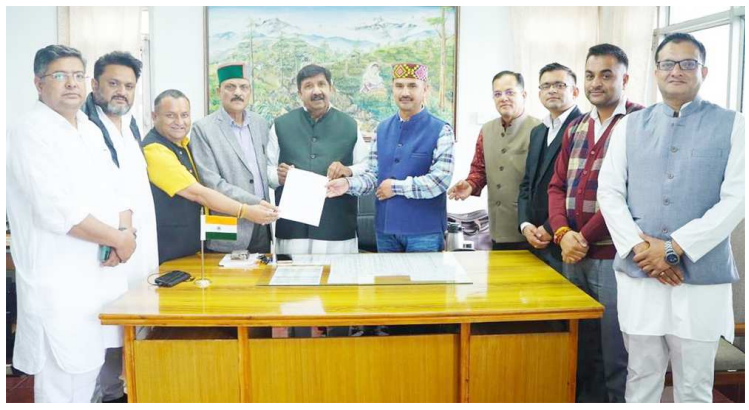

लाल की ओर से याचिका दायर की गई जिसमें विधान सभा अध्यक्ष से दोनों विधायकों की सदस्यता रद्द करने की मांग की गई।

नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने कहा है कि याचिका में दलबदल कानून के तहत इन दोनों निर्दलीय विधायकों प्रकाश राणा और होशियार सिंह राणा की सदस्यता रदद करने की मांग की गई है। उन्होंने कहा कि दोनों विधायकों ने संशोधित दलबदल कानून का उल्लंघन किया है। आर्टिकल दो और तीन में स्पष्ट लिखा है कि कोई भी व्यक्ति यदि किसी राजनीतिक दल के खिलाफ चुनाव जीतता है तो वह निर्वाचित विधायक तब तक किसी भी राजनैतिक दल की सदस्यता नहीं ले सकता जब तक वह विधान सभा की सदस्यता से त्यागपत्र नहीं दे देता।

मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि प्रकाश राणा और होशियार सिंह राणा ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण करके भारत के संविधान की अनुसूचि 10 के आर्टिकल 102 (2) 191 (2) की सेक्शन 2 और 3 दल बदल कानून का उल्लंघन किया है। उन्होंने कहा कि आर्टिकल 2 और 3 में इस का स्पष्ट उल्लेख है।

इस मौके पर कांग्रेस विधायक दल के सचिव नंद लाल, विधायक विनय कुमार, आशीष बुटेल, भवानी पठानिया, प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता देवेन्द्र बुशैहरी, कांग्रेस लीगल सैल के कार्यकारी अध्यक्ष अधिवक्ता प्रणय प्रताप सिंह सहित पुनीत राजटा, विवके शर्मा तथा धनंजय सिंह उपस्थित थे।

हिमाचल प्रदेश में कृषि क्षेत्र प्रोत्साहन कोष के तहत नाबार्ड द्वारा 5 परियोजनाएं स्वीकृत

शिमला/शैल। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) हिमाचल प्रदेश क्षेत्रीय कार्यालय ने कृषि क्षेत्र प्रोत्साहन कोष(FSPF)के तहत अनुदान मोड के तहत निम्नलिखित 5 परियोजनाओं के लिए 65,61,885.00 रुपये की राशि मंजूर की है।

1. सीएसके हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय मधुमक्खी अनुसंधान केंद्र, नगरोटा बगवां द्वारा जिला कांगड़ा और चंबा में हिमाचल प्रदेश के किसानों द्वारा गुणवत्तापूर्ण शहद, पराग और मधुमक्खी के उत्पादन के लिए स्थिरता के लिए कौशल विकास और मधुमक्खी पालन में सुधार करना।

2. जी.बी. पंत राष्ट्रीय हिमालयी पर्यावरण संस्थान द्वारा लाहौल और स्पीति, हिमाचल प्रदेश में लाहौल और स्पीति घाटी में सीबकथॉर्न (हिप्पोफे रमनोइड्स) के मूल्य वर्धित उत्पादों के माध्यम से उद्यमिता और आजीविका का विकास करना।

3. मानव विकास संस्थान बिलासपुर द्वारा जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश के झंडुता प्रखंड में रेशम उत्पादन के माध्यम से ग्रामीण गरीबों की आजीविका में वृद्धि।

4. हिमालयी वन अनुसंधान संस्थान द्वारा हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले के चयनित वन रेंज में समुदाय आधारित दृष्टिकोण के माध्यम से देशी परागणकों और उनके खाद्य पौधों के संरक्षण के लिए प्रथाओं को बढ़ावा देने पर क्षमता निर्माण।

5. सर्व हिमालया सोसाइटी द्वारा उत्पादकता बढ़ाने के लिए सेब के पेड़ों के छत्र प्रबंधन पर जिला किन्नौर के सेब उत्पादकों का प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण।

इन परियोजनाओ के कार्यान्वित होने के पश्चात हिमाचल प्रदेश के 1340 किसानों को प्रशिक्षित कर राज्य में मधुमक्खी पालन, सेव के उत्पादन एवं रेशम उत्पादन के क्षेत्र में लाभ मिलेगा। उम्मीद है कि स्वयं सहायता समूहो को इन प्रशिक्षणों द्वारा सुदृढ़ किया जा सकेगा एवं हिमाचल में प्राकृतिक खेती के प्रयासो को बढ़ावा मिलेगा।

उच्च घनत्व सेब बगीचों के बारे में किसानों को किया गया अवगत

नौणी विवि में मनाया सेब दिवस

शिमला/शैल। डॉ यशवंत सिंह परमार औदयानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, नौणी के फल विज्ञान विभाग द्वारा विश्वविद्यालय परिसर में सेब दिवस एवं किसान मेला का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित हिमाचल प्रदेश बागवानी

विकास परियोजना(एचपी एचडीपी) के तहत राज्य के आठ जिलों में गठित विभिन्न समूहों के 200 से अधिक बागवानों और अन्य किसानों, और राज्य बागवानी विभाग के अधिकारियों ने भाग लिया। इस आयोजन का उद्देश्य उच्च घनत्व वाले सेब के बगीचे पर किसानों को अवगत करवाना और उनकी समस्याओं का समाधान करना था।

एचपी एचडीपी के राज्य नोडल अधिकारी डॉ. गोबिंद सिंह जोबटा ने विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित परियोजना के बारे में और उनकी उपलब्धियों और पहलों के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि इस परियोजना के तहत लगभग 5000 हेक्टेयर नए उच्च घनत्व वाले वृक्षारोपण और 1000 हेक्टेयर वैज्ञानिक रूप से प्रबंधित बागों को लगाने का लक्ष्य रखा गया है।

इस अवसर पर प्रोफेसर चंदेल ने विश्व स्तरीय अनुसंधान प्रयोगशालाओं और बगीचों की स्थापना के लिए वैज्ञानिकों की सराहना की और कहा कि वैज्ञानिकों के संयुक्त प्रयासों ने चार साल के उच्च घनत्व वाले वृक्षारोपण में 42 मीट्रिक टन से अधिक उत्पादकता सुनिश्चित की है जो वर्तमान उत्पादकता से काफी अधिक है। उन्होंने वैज्ञानिकों से कहा कि वे किसानों द्वारा हासिल उत्पादकता और विश्वविद्यालय की उत्पादकता के बीच की अंतर को दूर करने की दिशा में कार्य करें।

उन्होंने वैज्ञानिकों से विभिन्न कृषि पद्धतियों और तकनीकों का उपयोग करके नए बगीचे लगाने, मिट्टी और पानी पर प्रभाव सहित लागत-लाभ अनुपात का अध्ययन करने का आग्रह किया। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि छोटे और मध्यम किसानों के लिए भी विभिन्न वृक्षारोपण मॉडल स्थापित किए जाने चाहिए। प्रोफेसर चंदेल ने किसानों से वैज्ञानिकों के साथ अपनी सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने का अनुरोध किया ताकि इनका अध्ययन कर विश्वविद्यालय द्वारा कृषक समुदाय द्वारा उपयोग के लिए इसका प्रसार किया जा सके।

वर्ष 2016 में लगाए गए उच्च घनत्व वाले सेब के बागानों का एक क्षेत्र दौरा भी आयोजित किया गया। इस बगीचे में जेरोमाइन, रेड वेलोक्स, रेड कैप वाल्टोड, स्कारलेट स्पर-II, सुपर चीफ, गेल गाला, रेडलम गाला और एविल अर्ली फूजी जैसी विभिन्न किस्मों को M9 और MM106 रूटस्टॉक्स पर अलग-अलग दूरी और प्रशिक्षण प्रणालियों में लगाया गया है।

फल विज्ञान विभाग के एचओडी डॉ. डीपी शर्मा ने बताया कि विभाग के वैज्ञानिकों ने क्षेत्र भ्रमण के दौरान किसानों के समक्ष आ रही समस्याओं का समाधान किया। विस्तार शिक्षा निदेशालय में किसान-वैज्ञानिक परिचर्चा भी आयोजित की गई जिसमें विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने पोषक तत्व प्रबंधन, कीट और कीट, रोग और समग्र बाग प्रबंधन पर किसानों के प्रश्नों को संबोधित किया।

किसानों ने सुझाव दिया कि विश्वविद्यालय का साहित्य हिंदी और अंग्रेजी में उपलब्ध होना चाहिए। प्रतिभागियों ने यह भी अनुरोध किया कि उन्हें रूटस्टॉक्स उपलब्ध करवाए जाने चाहिए और विभिन्न स्थानों पर ट्रेनिंग और छंटाई के शिविर आयोजित किए जाने चाहिए। डॉ शर्मा ने बताया कि इस वर्ष विश्वविद्यालय किसानों को सीडलिंग रूटस्टॉक्स के अतिरिक्त क्लोनल रूटस्टॉक्स पर 10,000 से अधिक ग्राफ्टेड पौधे उपलब्ध कराएगा।

प्रदेश सरकार ने आम व नींबू प्रजाति के फलों के लिए मण्डी मध्यस्थता योजना को मंजूरी दी

शिमला/शैल। राज्य सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि प्रदेश सरकार ने वर्ष 2022 के लिए प्रसंस्करण श्रेणी के आम के प्रापण के लिए मंडी मध्यस्थता योजना लागू कर दी है। उन्होंने बताया कि योजना के तहत 250 मीट्रिक टन सीडलिंग आम 10.50 रुपये प्रति किलो, 500 मीट्रिक टन ग्राफ्टेड आम 10.50 रुपये प्रति किलो और 500 मीट्रिक टन आचारी किस्म के आम का 10.50 रुपये प्रति किलो की दर से प्रापण किया जाएगा।

फलों का प्रापण एचपीएमसी और हिमफेड द्वारा क्रेट्स में किया जाएगा और इन एजेंसियों को 1.30 रुपये प्रति किलो की दर से हैंडलिंग चार्जिज की अनुमति होगी। उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष की तरह सीडलिंग आम का औसत विक्रय रिटर्न प्रति लाभ 2500 रुपये प्रति मीट्रिक टन, आचारी आम का 2500 रुपये प्रति मीट्रिक टन और ग्राफ्टेड आम का 3500 रुपये प्रति मीट्रिक टन की दर से आंकलन किया गया है।

योजना के तहत 42 फल प्रापण केंद्र खोले जाएंगे। एचपीएमसी और हिमफेड द्वारा पिछले तीन से पांच वर्षो के प्रापण डेटा के आधार पर प्रापण केंद्र स्थापित करने के लिए समन्वय किया जाएगा। यह केंद्र प्रापण एजेंसियों द्वारा खोले जाएंगे और इनका संचालन एचपीएमसी और हिमफेड के स्टाफ द्वारा किया जाएगा।

उन्होंने बताया कि योजना के तहत वाष्पोत्सर्जन व हेंडलिंग प्रक्रिया के नुकसान के दृष्टिगत बागवानों/ उत्पादकों से भार के आधार पर 2.5 प्रतिशत फलों का अतिरिक्त प्रापण किया जाएगा। योजना के तहत उन किसानों/बागवानों से फलों का प्रापण किया जाएगा जिनके पास बागवानी कार्ड और आम उत्पादन के तहत 10 बीघा या इससे कम जमीन है। ठेकेदारों से किसी भी फल का प्रापण नहीं किया जाएगा। राज्य में यह योजना एक जुलाई से 31 अगस्त, 2022 तक कार्यान्वित की जाएगी।

प्रवक्ता ने बताया कि प्रदेश सरकार ने वर्ष 2022-23 के लिए नीम्बू प्रजाति के फलों जैसे किन्नू, मालटा, संतरा और गलगल के प्रापण के लिए भी मंडी मध्यस्थता योजना लागू करने के लिए स्वीकृति प्रदान कर दी है। यह योजना 21 नवम्बर, 2022 से 15 फरवरी, 2023 तक लागू होगी।

उन्होंने बताया कि योजना के अन्तर्गत 500 मीट्रिक टन किन्नू/मालटा/संतरा का प्रापण श्रेणी-बी का 9.50 रुपये प्रति किलो ग्राम एवं श्रेणी-सी का 9.00 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से तथा 100 मीट्रिक टन गलगल का प्रापण 8.00 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से किया जाएगा। किन्नू/मालटा/संतरा के लिए 2.65 रुपये प्रति किलो ग्राम तथा गलगल के लिए 1.00 रुपये प्रति किलो ग्राम की दर से हैंडलिंग चार्जिज दिए जाएंगे।

उन्होंने बताया कि कल्पित विक्रय वसूली को किन्नू, माल्टा, संतरा के लिए 3.50 रुपए प्रति किलोग्राम तथा गलगल के लिए 1.50 प्रति किलोग्राम रखा जाएगा। इस योजना के अंतर्गत कुल 52 प्रापण केन्द्र मांग के आधार पर खोले जाएंगे तथा आवश्यकता के आधार पर बाद में और प्रापण केन्द्र खोले जाएंगे जिनका संचालन एचपीएमसी व हिमफैड अपने स्टाफ द्वारा ही करेंगे। भण्डारण व यातायात के नुकसान इत्यादि की भरपाई को ध्यान में रखते हुए इस योजना के अंतर्गत इस वर्ष भी फलों का प्रापण 2.5 प्रतिशत अधिक फल सहित किया जाएगा।

प्रदेश सरकार ने सेब की खरीद के लिए मण्डी मध्यस्थता योजना स्वीकृत की

शिमला/शैल। उद्यान विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि प्रदेश सरकार ने वर्ष 2022 के दौरान हिमाचल प्रदेश में सेब खरीद के लिए मण्डी मध्यस्थता योजना के क्रियान्वयन को स्वीकृति प्रदान की है।

उन्होंने कहा कि वर्ष 2022 के लिए मण्डी मध्यस्थता योजना के अन्तर्गत 1,44, 936 मीट्रिक टन सेब के लिए प्रापण मूल्य 10.50 रुपये प्रति किलो रहेगा।

उन्होंने कहा कि हैंडलिंग चार्जिज़ 2.75 रुपये प्रति किलो और अनुमानित बिक्री प्राप्ति 3.50 प्रतिकिलो माना जाएगा। उन्होंने कहा कि योजना के अन्तर्गत फल बागवानों की मांग के अनुरूप 305 प्रापण केन्द्र खोले जाएंगे, जिस में से एचपीएमसी द्वारा 169 केन्द्र खोले तथा संचालित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि 136 केन्द्र हिमफेड के कर्मचारियों द्वारा संचालित किए जाएंगे, जिसके लिए उद्यान विभाग ने 259.84 लाख रुपये की निधि प्रस्तावित की है।

उन्होंने कहा कि इस योजना के अन्तर्गत 35 किलो की क्षमता वाले गनी बैग में फल खरीदे जाएंगे। वाष्पोत्सर्जन की हानि को देखते हुए 2.5 प्रतिशत अधिक फलों की खरीद की जाएगी। योजना के अन्तर्गत केवल 51 एमएम से अधिक व्यास वाले सेबों की खरीद की जाएगी। उन्होंने कहा कि जिन फलों का छिलका फटा हुआ होगा या पक्षियों द्वारा खाए गए/क्षतिग्रस्त फलों की खरीद नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि कीट, कीड़ों और फंफूद रोग से ग्रस्त फल जिनमें स्कैब, एथरल स्प्रे वाले फल शामिल हैं, कच्चे एवं अधिक पके फलों को भी स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसी प्रकार, गम्भीर रूप से कटे फलों को भी स्वीकार नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हल्की ओलावृष्टि, हल्की चोट, गेरूए और विकृत आकृति वाले फलों को स्वीकार किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि प्रदेश में मण्डी मध्यस्थता योजना 20 जुलाई से 31 अक्तूबर, 2022 तक क्रियान्वित की जाएगी।

युवा सेवा एवं खेल विभाग अनुरोध करता है कि उक्त फिट इंडिया एप को डाउनलोड करें तथा अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित करें |

श्री राजेश शर्मा (भा०व०से०),
निदेशक,
युवा सेवा एवं खेल, हि० प्र०

सम्पादक, प्रकाशक एवं मुद्रक श्री बलदेव शर्मा द्वारा ऋचा प्रिंटर्ज एण्ड पब्लिशर्ज़ रिवोली बस अड्डा लक्कड़ बाजार शिमला से प्रकाशित व मुद्रित दूरभाष: 0177 – 2805015, 94180 – 15015 फैक्स: 2805015

क्या आप प्रदेश में चुनाव लड़ने के प्रति गंभीर है

- सिराज में रैली करने की घोषणा क्यों पूरी नहीं हो रही
- भाजपा और कांग्रेस के कार्यकालों में शिक्षा और स्वास्थ्य में हुए घोटालों पर चुप्पी क्यों
- शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार का ब्लू प्रिंट क्या है?
- क्या कुछ लोग संघ भाजपा से निर्देशित है

शिमला/शैल। इन दिनों दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार और केंद्र सरकार के बीच टकराव चल रहा है। केजरीवाल को सिंगापुर जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है। दिल्ली सरकार की आबकारी नीति की जांच सीबीआई से करवाने की सिफारिश उप राज्यपाल कर चुके हैं। हिमाचल के प्रभारी रहे सत्येंद्र जैन ईडी की हिरासत में चल रहे हैं। पंजाब में मुस्से वाला की हत्या के बाद पंजाब में कानून और व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े किये जा रहे हैं। पंजाब में राघव चड्डा की अध्यक्षता में बनाई सलाहकार कमेटी को अदालत में चुनौती दी जा चुकी है। केजरीवाल के मॉडल को रेवड़िया बांटना करार देकर प्रधानमंत्री इससे बचने की सलाह दे चुके हैं। यह सब कितना सही या गलत है इसका पता तो आने वाले समय में ही लगेगा। लेकिन अभी जनता केजरीवाल के अच्छी शिक्षा व्यवस्था और अच्छे स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाने तथा भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन देने के वायदों से प्रभावित होकर उसके गिर्द इक्ठी हो ही रही है। इसका ताजा उदाहरण सोलन की प्रस्तावित रैली थी। इसमें केजरीवाल खराब मौसम के कारण शामिल नहीं हो सके। लेकिन इसके बावजूद सोलन में मौसम के खराब होते हुये भी 10000 लोगों का आना अपने में इस बात का प्रमाण है कि लोग बदलाव चाहते हैं। जनता में भाजपा और कांग्रेस दोनों के प्रति रोष है। इस रोष को यदि सही दिशा मिल गई तो इसके परिणाम निश्चित रूप से चौंकाने वाले हो सकते हैं। इस परिपेक्ष में यह आवश्यक हो जाता है कि आप जब लोगों से यह वायदे कर रही है तो इसी के साथ उससे यह भी पूछा जाये कि इन वायदों को पूरा करने के लिये आर्थिक संसाधन कहां से आयेंगे? क्या इसके लिये जनता पर करों का बोझ डाला जायेगा या उसके सिर कर्ज का भार बढ़ाया जायेगा। क्योंकि केंद्र से वही आर्थिक सहायता मिलेगी जो नियमानुसार राज्य का हक होगा। अभी पंजाब की जो आर्थिक स्थिति चल रही है उसमें किस तरह से चुनाव में किये गये वायदों को पूरा किया जाता है यह देखना भी दिलचस्प होगा। क्योंकि पंजाब उन तेरह राज्यों की सूची में शामिल है जो आरबीआई के मुताबिक कर्ज लेन की सारी सीमाएं लांघ चुके हैं। यदि केंद्र इन राज्यों की सहायता नहीं करता है तो उनकी स्थिति श्रीलंका जैसी हो सकती है। यह चेतावनी रिजर्व बैंक की है। हिमाचल में भी कर्ज कैग के मुताबिक सीमाएं लांघ चुका है। ऐसे में जनता अभी तो लोकलुभावन वायदों से प्रभावित हो सकती है जैसे मोदी के अच्छे दिन और पन्द्रह-पन्द्रह लाख

हरेक के खातों में आने से प्रभावित हुये थे। जबकि आज साधारण खाद्य पदार्थों पर भी जीएसटी लगाने की नौबत आ गयी है। ऐसे में आज प्रदेश में आप के प्रति जो रुझान जनता का कुछ-कुछ बनता जा रहा है उसमें जनता के सामने राज्य की व्यावहारिक स्थिति रखना आप के स्थानीय नेतृत्व की जिम्मेदारी हो जाती है। लेकिन स्थानीय नेतृत्व शिक्षा और स्वास्थ्य के मंत्र जाप से आगे बढ़ नहीं पा रहा है। इसमें भी वह यह ब्लू प्रिन्ट सामने नहीं ला पाया है कि सुधार संभव होगा कैसे? इसमें यह संदेश उभर रहा है की या तो स्थानीय नेतृत्व को प्रदेश की जानकारी ही नहीं है या वह फिर कहीं भाजपा से निर्देशित तो नहीं हो रहा है। क्योंकि मण्डी में मुख्यमंत्री के अपने विधानसभा क्षेत्र सिराज में जो जयराम को घेरने के लिये रैली करने की घोषणा सत्येंद्र जैन की थी अब लगता है कि इस घोषणा को नेतृत्व भूल ही गया है। यही नहीं शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्रों में भाजपा और कांग्रेस के शासन कालों में क्या-क्या घोटाले हुये हैं उन पर भी जनता के सामने न तो कोई जानकारियां रखी जा रही है न ही उन पर कोई सवाल पूछे जा रहे हैं। इस समय तो यही आकलन बन रहा है कि आप प्रदेश विधान का चुनाव बहुत गंभीरता से नहीं लड़ना चाह रहा है। जबकि इस समय भी आप में कुछ लोग ऐसे हैं जो आर एस एस की प्रदेश इकाई की हर गतिविधि और रणनीति की जानकारी रखते हैं। बल्कि चर्चा तो यहां तक है कि यह लोग वाकायदा संघ की अनुमति लेकर ही आप में शामिल हुये हैं। शायद इन्हीं कारणों से आप का प्रदेश में आगे बढ़ना रुक सा गया है।

क्यों नहीं आ रहा है कांग्रेस का आरोप पत्र

- शान्ता कुमार की आत्मकथा में ही भाजपा सरकार पर लगाये गये आरोपों पर भी क्यों चुप है प्रदेश कांग्रेस
- क्या रस्मी धरना प्रदर्शनों से ही कांग्रेस सफल हो जायेगी?

शिमला/शैल। इस समय राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस ही भाजपा को सीधी चुनौती दे रही है। अन्य विपक्षी दल इसमें बहुत पीछे चल रहे हैं। बल्कि यह कहना ज्यादा सही होगा कि अन्य दलों में तोड़फोड़ करके उन को कमजोर करने की रणनीति पर सरकार और भाजपा चल रही है। कांग्रेस नेतृत्व को ईडी में उलझाने की कवायद की जा रही है। कांग्रेस में पहले राहुल गांधी और अब सोनिया गांधी को ईडी द्वारा पूछताछ के लिये बुलाया जाना इसके प्रमाण हैं। कांग्रेस ईडी को लेकर पूरी आक्रामकता के साथ देशभर में विरोध प्रदर्शन आयोजित कर रही है। नेतृत्व का एक वर्ग ईडी मामले की सच्चाई भी जनता के सामने रखता जा रहा है ताकि जनता को यह विश्वास दिलाया जा सके कि इस मामले में इन नेताओं को जबरदस्ती उलझाया जा रहा है। कांग्रेस के लिये यह एक बड़ा मुद्दा बन गया है और यह आवश्यक हो गया है कि सरकार और भाजपा को उसके ही भ्रष्टाचार पर घेरा जाये। यह कहने के लिये जिन राज्यों में भाजपा की सरकारें हैं वहां की कांग्रेस ईकाईयों को भी इस में सक्रिय भूमिका निभानी होगी। हिमाचल में भाजपा की सरकार है और कांग्रेस मुख्य विपक्षी दल है। लेकिन यह एक अजीब संयोग है कि कांग्रेस इस सरकार के खिलाफ अभी तक कोई आरोप पत्र जारी नहीं कर पाई है। पिछले दिनों जब यह चर्चा उठी कि कांग्रेस जल्द ही सरकार के खिलाफ ठोस तथ्य पर आधारित एक आरोप पत्र राज्यपाल को सौंपने जा रही है। यह चर्चा सामने आते ही मुख्यमंत्री का यह ब्यान आ गया कि वह कांग्रेस सरकार के खिलाफ एक समय भाजपा द्वारा सौंपे आरोप पत्र की जांच सीबीआई द्वारा करवाने पर विचार कर रहे हैं। मुख्यमंत्री के इस ब्यान के बाद कांग्रेस का अपेक्षित आरोपपत्र फिर चर्चा से गायब हो गया है। जबकि एक समय यही कांग्रेस सदन में जयराम सरकार पर हिमाचल बेचने का आरोप लगा चुकी है। कांग्रेस के समय में एकल खिड़की योजना के तहत पारित हुये सीमेंट उद्योग जयराम सरकार में कैसे लालफीताशाही का शिकार हुये हैं। इसको लेकर प्रोमोटर शिकायत तक कर चुके हैं। लेकिन कांग्रेस इन मुद्दों पर एकदम चुप चल रही है और इस चुप्पी को लेकर अब सवाल उठने शुरू हो गये हैं। भाजपा सरकार के खिलाफ एक समय केंद्र में मंत्री रहे शान्ता कुमार ने अपनी आत्मकथा में बहुत ही गंभीर आरोप लगाये हुये हैं। शान्ता ने यहां तक आरोप लगाया है कि इस भ्रष्टाचार की जांच की मांग करने के कारण ही उन्हें वाजपेयी मंत्रिमण्डल से हटा दिया गया था। शान्ता कुमार ने अपनी आत्मकथा में सरकार से लेकर अब की मोदी सरकार के खिलाफ भी गंभीर आरोप लगाये हैं। यदि प्रदेश की कांग्रेस इकाई शान्ता कुमार की आत्मकथा में उठाये गये मुद्दों पर ही मोदी सरकार से प्रश्न पूछने का साहस जुटा पाती है तो उसी से केंद्र सरकार कटघरे में खड़ी हो जाती है। क्योंकि यह आरोप तो स्वयं भाजपा के ही केंद्र में मंत्री रहे व्यक्ति द्वारा लगाये गये हैं। लेकिन प्रदेश कांग्रेस का सारा नेतृत्व जिस तरह से केंद्र से निर्देशित धरना प्रदर्शनों तक ही अपने को सीमित रख रही है उससे कई सवाल उठने शुरू हो गये हैं।